

युवाओं के सॉलिड डीप टेक आइडिया को पैसा और बाजार दिलाएगा आईआईटी

आईआईटी इंदौर और आईएफसीआई वेंचर के बीच हुआ एमओयू साइन

इंदौर | कई युवाओं के पास स्टार्टअप के लिए बेहतरीन आइडिया होते हैं, लेकिन पैसों की कमी और सही गाइडेंस की कमी से शुरुआत नहीं हो पाती। अब ऐसे आइडिया पर आईआईटी इंदौर अब स्टार्टअप को सिर्फ तकनीकी मदद ही नहीं देगा, बल्कि उन्हें सरकारी फंडिंग दिलाने और उनके प्रोडक्ट को बाजार में उतारने की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इसके लिए आईआईटी इंदौर के दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन और भारत सरकार के उपक्रम आईएफसीआई वेंचर के बीच एक एमओयू हुआ है। इसका मकसद होनहार स्टार्टअप की आर्थिक बाधाओं को दूर करना है।

इस समझौते का सीधा लाभ उन युवाओं को मिलेगा, जो डीप-टेक, डिजिटल हेल्थकेयर या तकनीक पर आधारित कोई इनोवेशन कर रहे हैं। करार के जरिए भारत सरकार की खास फंडिंग योजनाओं का पैसा स्टार्टअप तक आसानी से पहुंचेगा। इसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों पर खास फोकस रहेगा। उन्हें वेंचर कैपिटल फंड और सेज जैसी सरकारी योजनाओं के जरिए अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए मदद दिलाई जाएगी। इसके साथ ही ऐसे स्टार्टअप भी पात्र होंगे, जिनका प्रोडक्ट समाज की किसी असल चुनौती को दूर करता हो और जिसे बाजार में बड़े पैमाने पर उतारा जा सके।

सिर्फ पैसा नहीं, बिजनेस करना भी सिखाएंगे

कई बार स्टार्टअप वालों की तकनीक तो अच्छी होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि बड़े इन्वेस्टर्स के सामने अपने आइडिया को कैसे पिच करना है। आईआईटी और आईएफसीआई मिलकर ऐसे स्टार्टअप की पहचान करेंगे। उन्हें बिजनेस की बारीकियां सिखाएंगे, इन्वेस्टर्स से उनकी सीधी मुलाकात करवाएंगे और लैब में बने उनके प्रोडक्ट को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार करेंगे।

लैब और कागजों से बाहर निकलेगी रिसर्च

आईआईटी इंदौर के डायरेक्टर प्रो. सुहास जोशी का साफ कहना है कि रिसर्च सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस करार का मकसद यही है कि युवाओं के ऐसे आइडियाज को पैसा और बाजार मिले, जो समाज की असल चुनौतियों को दूर कर सकें। दृष्टि फाउंडेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रो. आईए पलानी के मुताबिक, यह करार युवाओं के नए प्रयोगों को सीधे बाजार के बड़े मौकों और इन्वेस्टर्स से जोड़ने का एक पक्का रास्ता बनेगा।

फंडिंग के लिए स्टार्टअप के चयन की यह है प्रक्रिया

- पहचान और स्क्रीनिंग: आईआईटी और आईएफसीआई की टीम मिलकर ऐसे स्टार्टअप की खोज करेगी, जिनके आइडिया में दम है।
- जांच-परख (ड्यू डिलिजेंस): हर स्टार्टअप के प्रस्ताव को सरकारी योजनाओं की गाइडलाइंस और नियमों के आधार पर परखा जाएगा। देखा जाएगा कि वे योजना की शर्तों पर खरे उतरते हैं या नहीं।
- तैयारी और पिचिंग: शुरुआती चयन के बाद, आईआईटी इंदौर इन स्टार्टअप को इन्वेस्टर्स के सामने अपना बिजनेस मॉडल पेश पिच करने के लिए पूरी तरह तैयार करेगा।
- फाइनल अप्रूवल: सभी मापदंड पूरे करने और फंड की उपलब्धता के आधार पर केस-टू-केस (अलग-अलग) फाइनल अप्रूवल दिया जाएगा।

तकनीक व स्वास्थ्य के स्टार्टअप को क्यों है सबसे ज्यादा जरूरत?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तकनीक और स्वास्थ्य (डीप-टेक) से जुड़े प्रोडक्ट बनाने में सालों की रिसर्च लगती है, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टर शुरुआत में पैसा लगाने से बचते हैं। ऐसे में यह सरकारी फंडिंग युवाओं को बिना किसी दबाव के अपना प्रोडक्ट तैयार करने की आजादी देती है। वहीं, आईआईटी का नाम और नेटवर्क उस प्रोडक्ट को सीधे सही बाजार तक पहुंचा देता है। दोनों का यह तालमेल स्टार्टअप को शुरुआत में ही दम तोड़ने से बचाता है और उन्हें तेजी से आगे बढ़ाता है।